

एक सदस्य बोल रहा है तो दूसरे सदस्य को बीच में बोलने को ...(व्यवधान) ... कृपया दूसरे को भी ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There are certain names. But I have not called them also. Kindly bear with me.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, I abide by your decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly bear with me. Those Members who have been given permission to raise issues, they have to be called first.

RE: RALLY OF AGRICULTURAL WORKERS

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिम बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सदन का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहूंगा कि आज सैकड़ों-हजारों खेत मजदूर देश के कोने-कोने से राजधानी की सड़कों पर आ चुके हैं। वह अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं, अपनी मांगों के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे देश के खेतिहर मजदूर न सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे पिछड़ा हुआ तबका है और यह हमारे लिए एक दर्दनाक बात है कि अभी जो सरकार आई है इस प्रकार के आने के पहले सभी पार्टियों ने मिलकर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, उसमें भी हमने यह बात शामिल की थी कि हमारे देश के खेतिहर मजदूरों के लिए जो न्यूनतम वेतन की मांग है उसके लिए एक कानून केन्द्रीय सरकार की ओर से आना चाहिए। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और जो इस सरकार का समर्थक दल है, वह भी सदन के अन्दर यह वायदा कर चुका था कि ऐसा केन्द्रीय कानून होना चाहिए क्योंकि खेतिहर मजदूरों की बहुत ही कमजोर और नाजुक स्थिति है। अगर उन्हें किसी कानून का सहारा नहीं मिलेगा तो खेतिहर मजदूर अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पायेंगे। इसलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में हम अखबारों में तरह-तरह की बातें देख रहे हैं कि यह कब होगा इसके बारे में कुछ साफ नहीं है इसलिए सरकार के मंत्रीगण जो हैं वे कम से कम इस बारे में वायदा करें, क्योंकि आज हजारों खेतिहर मजदूर सड़क पर आये हैं।

दूसरा सवाल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का है। आज वे यह मांग कर रहे हैं कि कम से कम 60 रूपया उनका वेतन होना चाहिए और उनकी दैनिक मजदूरी को भी मुद्रास्फीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा सवाल उनका यह है कि सरकार की तरफ से उनको जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज मिलता है और जो आधे दाम पर अनाज मिलने का सवाल है, वह अनाज भी उनको मिलना चाहिए। पीडीएस के तहत शारीरिक काम करने वाले लोगों को ज्यादा अनाज मिलना चाहिए और इसमें मजदूरों को प्राथमिकता दी जाये। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन सवालों पर अपने विचार व्यक्त करे और अपना समर्थन दे।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Every issue is important and I will call Members who have given their names.

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे साथी श्री नीलोत्पल बसु जी ने जो शुद्ध हिन्दी में खेतिहर मजदूरों का सवाल उठाया है मैं अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में उसका समर्थन करता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि जब नरेन्द्र मोहन जी भी इस मामले के संबंध में खड़े हो गये तो इसमें कोई एतराज नहीं है। पिछले सत्र में कालिंग अटेंशन मोशन के जरिए इस बारे में चर्चा हुई थी और मंत्री महोदय ने यहां पर वायदा किया था। सवाल यह है कि पिछले सत्र के आखिरी दिन के अन्दर यह कानून आना चाहिए था और इस बजट सत्र को दो हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन इस पर सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। केबिनेट में यह सवाल गया है, ऐसा लगता है। लेकिन इससे पहले एग्रीकल्चरल और लेबर यूनियन से लेबर मिनिस्टर की बैठक हुई, बातचीत हुई, ड्राफ्ट तैयार हुआ लेकिन आज तक सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कह रही है। आई0 के0 गुजराल जी तो हैं वह तो नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चरल वर्कर्स में थे और उनकी रिकमेंडेशन है। मैंने यह कहा था कि हमारे देश में वृक्षों के लिए पशु-पक्षियों के लिए कानून है लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिए कोई कानून है लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है। हम आजादी का पचासवां साल मना रहे हैं और इस वर्षगांठ में यह कानून आना चाहिए, इसी सत्र में आना चाहिए।

شری محمد سلیم ”پشچمی بنگال“: آدرنیہ اپ سبھا ادھیکش جی۔ ہمارے ساتھی شری نیلوٹپیل بسو جی نے جو شد ہندی میں کھیتی پر مزدوروں کا سوال اٹھایا ہے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندی میں اسکا سمرتھن کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سریندر موہن جی بھی اس معاملے کے سمبندھ میں کھڑے ہو گئے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پچھلے ستر میں ”کالنگ ائینشن موشن“ کے ذریعہ اس بارے میں چرچ ہوئی بھی اور منتری مہودے نے یہاں پر وعدہ کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے ستر میں آخری دن کے انودیہ قانون آنا چاہئے تھا اور اس بجٹ ستر کو دو ہفتہ گزر چکے ہیں لیکن اس پر سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا ہے۔ کینٹ مینیو سوال کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایگریکلچرل اور لیبریونین سے لیبر منسٹر جی کی بیٹھک ہوئی۔ بات چیت ہوئی۔ ڈرافٹ تیار ہوا۔ لیکن آج تک سرکار اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ آئی۔ کے۔ گجرال جی تو ہیں وہ تو ”نیشنل کمیشن آن ایگریکلچرل ورکس“ میں تھے اور انکی رکنڈیشن ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں دیش میں ورکنشوں کے لئے۔ پشو پکشیوں کیلئے قانون ہیں لیکن ”کھیتی ہر مزدوروں“ کیلئے کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم آزادی کا 50 واں سال منا رہے ہیں اور اس ”ورش گاتھ“ میں یہ قانون آنا چاہئے۔ اسی ستر میں آنا چاہئے۔ ”ختم شد“

श्री नरेन्द्र कुमार ओझा (बिहार): अभी पार्लियामेंट के बाहर हजारों मजदूर आये और इस हाउस में एक बार नहीं, दो बार, नहीं, तीन बार यह कहा गया कि शीघ्र कानून बनाया जायेगा। इसलिए हम समझते हैं कि इस बारे में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उसकी शीघ्र की परिभाषा क्या है? सरकार शीघ्र को कब तक शीघ्र समझती है। हम मांग करते हैं कि इसी सत्र के दौरान यह कानून बनाया जाना चाहिए। यह बताया गया था कि लॉ डिपार्टमेंट के अन्दर पेंडिंग है, वहां से क्लीयर हो गया, अब मंत्री मंडल के स्तर पर पेंडिंग है। इसलिए यह बताया जाए कि हाउस के अन्दर कानून बनाने के लिए कब पेश किया जा रहा है?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश):

सर, उस बैठक में मैं भी उपस्थित था...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Narendra Mohan, kindly take your seat. You don't have to associate yourself with every issue.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : उसमें यह वायदा किया गया था कि लॉ मिनिस्टर साहब इस सत्र में इसको लायेंगे। लेकिन अभी तक खेतिहर मजदूरों का मामला क्यों नहीं ल गया है? वह समझ में नहीं आता है। सभी ट्रेड यूनियन्स के रिप्रजेंटेटिव और हर पार्टी के एमपी0 वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसके आधार पर बिबल भी तैयार हो गया है। कृपया आप सरकार को आदेश दें कि यह बिल शीघ्र ही आना चाहिए मजदूरों की सुरक्षा के लिए।

1.00 P.M.

RE: ISI'S MACHINATIONS TO
DESTABILISE J & K GOVERNMENT

प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) : महोदय, मैं देश के अलग-अलग हिस्सों में आईएसआई की एकदम तेजी से बढ़ती हुई ऐक्टिविटीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस श्री कुलदीप खुडा ने परसों एक प्रेस कान्फ्रेंस में यह कि आईएसआई ने आतंकवादियों को नियुक्त किया है कि मंत्रियों और विधान सभा सदस्यों की हत्या की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि आईएसआई के संदेश पकड़े गये हैं जिनमें राजनीजिज्ञों की हत्या के निर्देश दिये हैं। हिजब-उल, मुजाहदीन मोहम्मद युसूफ जो पुलिस से